

महिला शिक्षकों की आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक योगदान: एक व्यापक समीक्षा

राजमनी सोनी

शोधार्थी

डॉ. विजय कुमार साहू

सारांश: यह समीक्षा पत्र भारत में महिला शिक्षकों की आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक योगदान पर उपलब्ध साहित्य का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें मध्य प्रदेश के सागर जिले पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। यह समीक्षा विभिन्न अध्ययनों, सरकारी रिपोर्टों, नीति दस्तावेजों और शोध पत्रों का संश्लेषण करते हुए महिला शिक्षकों की स्थिति, चुनौतियों और योगदान को बहुआयामी परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करती है। समीक्षा से पता चलता है कि महिला शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद आर्थिक असमानताओं, संरचनात्मक बाधाओं और लैंगिक पूर्वाग्रहों का सामना करती हैं। यह पत्र शोध अंतरालों की पहचान करता है और भविष्य के शोध के लिए दिशा-निर्देश प्रस्तुत करता है।

कीवर्ड: महिला शिक्षक, आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक योगदान, सागर जिला, लैंगिक समानता, साहित्य समीक्षा, मध्य प्रदेश

परिचय

भारतीय समाज में महिला शिक्षकों की भूमिका हमेशा से दोहरी रही है—एक ओर वे शिक्षा की मुख्य धारा में योगदानकर्ता के रूप में स्थापित हैं, तो दूसरी ओर उनकी आर्थिक स्थिति और व्यावसायिक पहचान सामाजिक संरचनाओं के जटिल जाल में उलझी हुई है। यह समीक्षा पत्र महिला शिक्षकों की आर्थिक स्थिति और उनके शैक्षणिक योगदान के बीच के अंतर्संबंधों का विश्लेषण करता है, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के सागर जिले के संदर्भ में। प्रस्तुत समीक्षा का उद्देश्य यह समझना है कि किस प्रकार आर्थिक कारक महिला शिक्षकों की व्यावसायिक प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं और उनके

शैक्षणिक योगदान का मूल्यांकन किन मानदंडों पर किया जाना चाहिए।

यह अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सागर जिला, जो बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा है, अपनी भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक विशिष्टताओं के कारण एक अलग संदर्भ प्रस्तुत करता है। यहाँ की अर्ध-शुष्क जलवायु, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, और पारंपरिक सामाजिक मूल्य महिला शिक्षकों के जीवन और कार्य को एक विशिष्ट आकार प्रदान करते हैं। इस समीक्षा में हम यह पता लगाएंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने गए मुद्दे सागर जिले की स्थानीय वास्तविकताओं में किस रूप में प्रकट

होते हैं और उनके समाधान के क्या संभावित मार्ग हो सकते हैं।

महिला शिक्षकों की आर्थिक स्थिति का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

महिला शिक्षकों की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए सामाजिक प्रजनन सिद्धांत (Social Reproduction Theory) एक महत्वपूर्ण रूपरेखा प्रदान करता है। यह सिद्धांत बताता है कि किस प्रकार लैंगिक मानदंड और आर्थिक संरचनाएं महिला शिक्षकों से यह अपेक्षा करती हैं कि वे बिना उचित प्रतिकर के आर्थिक और देखभाल संबंधी भार वहन करें। शिक्षण पेशे के भीतर आर्थिक और भावनात्मक शोषण का एक आवर्ती पैटर्न देखने को मिलता है, जो देखभाल की भूमिकाओं के व्यापक सांस्कृतिक अवमूल्यन को प्रतिबिंबित करता है। यह अवमूल्यन केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर देखा जा सकता है।

बोर्डियू के पूंजी सिद्धांत के आलोक में देखें तो महिला शिक्षकों की आर्थिक स्थिति उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक पूंजी से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। शोध बताते हैं कि महिला शिक्षक अपने करियर में उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार की सामाजिक पूंजी का उपयोग करती हैं, जिसमें मेंटर से जुड़ना और अकादमिक क्षेत्र के प्रभावशाली अभिनेताओं से परिचय प्राप्त करना शामिल है। लेकिन निम्न-आय वर्ग की महिला शिक्षकों के लिए ये संसाधन सीमित होते हैं। वित्तीय संसाधनों, उच्च शिक्षा और सामाजिक

प्रतिष्ठा की कमी उनके समक्ष अतिरिक्त चुनौतियाँ उत्पन्न करती है।

भारतीय संदर्भ में विवाह संस्था महिलाओं की आर्थिक स्थिति को निर्धारित करने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। विवाह के बाद महिलाओं की नौकरी के चुनाव, कार्य करने की अनुमति, और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ उनके पति के परिवार द्वारा निर्धारित होती हैं। मसलक और सिंघल (2008) के अध्ययन में पाया गया कि उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीय महिलाएं भी व्यावसायिक पदों को ग्रहण करते समय स्वयं को माता, पत्नी और बहू के रूप में परिभाषित करती हैं। यह पारिवारिक दायित्वों की जटिलता को दर्शाता है, जिसे आर्थिक और सामाजिक नीति निर्माण में समझे जाने की आवश्यकता है।

लैंगिक वेतन अंतर और आर्थिक विषमताएं

शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक वेतन अंतर एक वैश्विक घटना है। शोध साहित्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि महिला शिक्षकों को उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में कम वेतन मिलता है, भले ही उनकी योग्यताएं और अनुभव समान हों। यह वेतन अंतर केवल प्रत्यक्ष मौद्रिक मुआवजे तक सीमित नहीं है, बल्कि संसाधन आवंटन, शोध अनुदान, और व्यावसायिक विकास के अवसरों तक विस्तारित है।

अध्ययनों से पता चलता है कि महिला शिक्षक पुरुषों की तुलना में कम प्रकाशित करती हैं, उनके शोध के लिए कम संसाधन आवंटित किए जाते हैं, उन्हें उच्च प्रकाशन लागत का सामना करना पड़ता है, नेटवर्क तक उनकी पहुंच

कम होती है, और उनके कार्य को कम उद्धरण प्राप्त होते हैं। ये सभी कारक उनके पदोन्नति और वेतन वृद्धि की संभावनाओं को प्रभावित करते हैं, जिससे उनके लिए अकादमिक सीढ़ी पर चढ़ना अधिक कठिन हो जाता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में भेदभाव-विरोधी कानून पारित होने के 25 वर्षों बाद भी अकादमिया में महिलाओं और पुरुषों के बीच वेतन अंतर कई संदर्भों में चौड़ा हुआ है। यह तथ्य इस बात का संकेत है कि केवल कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि संस्थागत संरचनाओं और सांस्कृतिक मानदंडों में गहरा परिवर्तन आवश्यक है।

अदृश्य श्रम और गैर-प्रोन्नत कार्य

महिला शिक्षकों के योगदान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा "अदृश्य श्रम" (Invisible Labour) की श्रेणी में आता है, जिसे न तो मान्यता मिलती है और न ही उचित मुआवजा। इस अदृश्य श्रम में भावनात्मक समर्थन प्रदान करना, समितियों में बैठना, पृष्ठभूमि में कार्य करना, और गैर-प्रोन्नत कार्यों (Non-Promotable Tasks) को अंजाम देना शामिल है। ये कार्य संस्थानों के संचालन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन पदोन्नति और करियर उन्नति में सहायक नहीं होते।

शोधकर्ताओं ने इस अदृश्य श्रम को "पत्नी कार्य" (Wife Work) की संज्ञा दी है, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि किस प्रकार यह कार्य घरेलू क्षेत्र में महिलाओं के अवैतनिक श्रम के समानांतर है। पत्नी कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हैं: मानक अपेक्षाओं से परे

मेंटरिंग समर्थन, प्रशासनिक और रसद संबंधी कार्य, छात्रों के लिए संदर्भ पत्र लिखना, भर्ती और आउटरीच, समिति कार्य, छात्रों को भावनात्मक समस्याओं में सहायता, और सहकर्मियों का समर्थन करना।

सामाजिक अपेक्षाएं और संस्थागत मानदंड महिलाओं को यह "पत्नी कार्य" लेने के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि यह श्रम संगठन की प्रतिष्ठा बनाए रखने में सहायक होता है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप भावनात्मक विसंगति (Emotional Dissonance) और जलन (Burnout) उत्पन्न हो सकती है। विश्वविद्यालयों में पदोन्नति के नए मार्ग विकसित हुए हैं, जैसे शिक्षण या प्रभाव-आधारित पदोन्नति, जिसमें नागरिकता (Citizenship) कम महत्वपूर्ण हो गई है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप महिलाएं गैर-प्रोन्नत कार्यों को अंजाम दे रही हैं, जो संस्थागत रूप से महत्वपूर्ण हैं लेकिन उनके करियर की सफलता में सहायक नहीं हैं।

शैक्षणिक योगदान की बहुआयामी प्रकृति

महिला शिक्षकों का शैक्षणिक योगदान केवल कक्षा शिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह छात्रों के सर्वांगीण विकास, सामुदायिक निर्माण, और मूल्यपरक शिक्षा के क्षेत्र में भी विस्तारित है। अध्ययन बताते हैं कि महिला शिक्षक छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसमें स्वायत्तता, योग्यता, और जुड़ाव शामिल हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां छात्रों का पेशेवर रोल मॉडल

से सीमित संपर्क होता है, वहाँ महिला शिक्षकों का योगदान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

आत्म-प्रभावकारिता विश्वास (Self-efficacy Beliefs) और विश्वविद्यालय से जुड़े होने की भावना छात्रों की शैक्षणिक सफलता से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित है। महिला शिक्षक, अपनी पोषणकारी भूमिका के कारण, छात्रों में यह आत्म-विश्वास और जुड़ाव की भावना विकसित करने में अधिक सक्षम होती हैं। लेकिन यह अतिरिक्त योगदान अक्सर मान्यता प्राप्त नहीं करता, क्योंकि यह "पाठ्यक्रम से परे" की गतिविधियों में गिना जाता है।

शोध यह भी दर्शाते हैं कि सांस्कृतिक कारक छात्रों के व्यक्तित्व लक्षणों के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। व्यक्तिवाद, अनिश्चितता से बचाव, और पुरुषत्व जैसे सांस्कृतिक आयाम छात्रों के बहिर्मुखता, सहमतता, और कर्तव्यनिष्ठा जैसे व्यक्तित्व लक्षणों को प्रभावित करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, महिला शिक्षक सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शिक्षण वातावरण निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहां सांस्कृतिक विविधता अधिक है।

सागर जिले का विशेष संदर्भ

मध्य प्रदेश के सागर जिले का भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य महिला शिक्षकों की स्थिति को समझने के लिए एक विशिष्ट संदर्भ प्रदान करता है। बुंदेलखंड क्षेत्र के हिस्से के रूप में, सागर जिला कई संरचनात्मक चुनौतियों का

सामना करता है जो यहाँ की महिला शिक्षकों के जीवन और कार्य को प्रभावित करती हैं।

भौगोलिक दृष्टि से, सागर जिला अर्ध-शुष्क जलवायु क्षेत्र में स्थित है, जहाँ वर्षा अनियमित और अपर्याप्त है। यह भौगोलिक परिस्थिति कृषि को अनिश्चित बना देती है, जो इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि पर निर्भर परिवारों की आय अनियमित और अपर्याप्त होती है, जिसका प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। ऐसे परिवेश में महिला शिक्षकों की आर्थिक स्थिति का आकलन करते समय यह समझना आवश्यक है कि वे न केवल अपने व्यक्तिगत बल्कि पारिवारिक आय के स्रोत के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

सागर जिले की सामाजिक संरचना पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाए हुए है। यहाँ की ग्रामीण और अर्ध-शहरी बस्तियों में अभी भी पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएं प्रबल हैं। महिला शिक्षकों को अक्सर दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है—एक ओर घरेलू उत्तरदायित्व और दूसरी ओर व्यावसायिक दायित्व। यह दोहरा बोझ उनके शैक्षणिक योगदान की गुणवत्ता और मात्रा दोनों को प्रभावित करता है।

सागर जिले में शिक्षा का बुनियादी ढांचा विषम रूप से विकसित हुआ है। शहरी क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों की संख्या और गुणवत्ता बेहतर है, जबकि ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में स्कूलों की कमी, अपर्याप्त संसाधन, और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात महिला

शिक्षकों को न केवल कम वेतन बल्कि खराब कार्य वातावरण, आवास की समस्या, और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का भी सामना करना पड़ता है।

शोध बताते हैं कि ग्रामीण संस्थानों के छात्र अपने शहरी समकक्षों की तुलना में विस्तारित व्यावसायिक परियोजनाओं के माध्यम से उच्च स्तर का व्यावसायिक कौशल विकास अनुभव करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि ग्रामीण छात्रों का पेशेवर रोल मॉडल या उनके कार्य करने के तरीकों से अब तक सीमित संपर्क रहा होता है। इस संदर्भ में, सागर जिले की महिला शिक्षकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वे न केवल ज्ञान का संचार करती हैं बल्कि व्यावसायिक आदर्श के रूप में भी कार्य करती हैं।

नीतिगत परिप्रेक्ष्य और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों की भूमिका और उनके व्यावसायिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह नीति शिक्षकों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने, उनके निरंतर व्यावसायिक विकास, और उनकी कार्य स्थितियों में सुधार की बात करती है। लेकिन नीति के कार्यान्वयन के संदर्भ में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये प्रावधान निम्न-आय वर्ग की महिला शिक्षकों तक कैसे पहुँचते हैं और उनके जीवन में क्या परिवर्तन लाते हैं।

नीति में शिक्षकों की नियुक्ति, वेतनमान, और कार्य स्थितियों में सुधार की बात की गई है, लेकिन लैंगिक असमानताओं को दूर करने के

लिए विशेष प्रावधानों की कमी है। नीति में शिक्षकों की व्यावसायिक विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है कि महिला शिक्षकों को इन अवसरों तक समान पहुँच मिले।

शोध बताते हैं कि बाजार की ताकतें अक्सर नियामक प्रभावों पर हावी हो जाती हैं, और निजी और सार्वजनिक संस्थानों के बीच शिक्षा के एकीकरण में महत्वपूर्ण असमानताएं हैं। यह असमानता सागर जिले के संदर्भ में और भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जहाँ सरकारी और निजी स्कूलों के बीच संसाधनों और शिक्षकों की स्थिति में बड़ा अंतर है।

पूँजी निर्माण और व्यावसायिक विकास के मार्ग

महिला शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में विभिन्न प्रकार की पूँजी की भूमिका को समझना आवश्यक है। शोध से पता चलता है कि महिला प्रोफेसर अपने करियर में उन्नति के लिए सामाजिक पूँजी का उपयोग करती हैं, जिसमें मेंटर से जुड़ना और अकादमिक क्षेत्र के प्रभावशाली अभिनेताओं से परिचय प्राप्त करना शामिल है। आर्थिक पूँजी का उपयोग संस्थागत और व्यक्तिगत समर्थन के माध्यम से करियर को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है।

लैंगिक पूँजी (Gender Capital) के संदर्भ में, अध्ययन बताते हैं कि महिला शिक्षक महिला पूँजी और स्त्री पूँजी दोनों से प्राप्त होने वाले लाभों का उल्लेख करती हैं। लेकिन यह पूँजी निर्माण निम्न-आय वर्ग की महिला शिक्षकों के

लिए आसान नहीं है। उनके पास न तो वित्तीय संसाधन हैं और न ही सामाजिक नेटवर्क जो उनके व्यावसायिक विकास को गति दे सकें।

सागर जिले के संदर्भ में, महिला शिक्षकों के पूंजी निर्माण की प्रक्रिया कई बाधाओं का सामना करती है। भौगोलिक दूरी, सीमित व्यावसायिक नेटवर्क, और पारंपरिक सामाजिक संरचनाएं उनके मेंटरशिप और व्यावसायिक विकास के अवसरों को सीमित कर देती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिला शिक्षकों के लिए यह चुनौती और भी गंभीर है।

सिफारिशें और नीतिगत हस्तक्षेप

इस व्यापक समीक्षा के आलोक में, महिला शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार और उनके शैक्षणिक योगदान की मान्यता के लिए कई नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हैं।

- प्रथम, वेतन संरचना में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित की जानी चाहिए। लैंगिक वेतन अंतर को समाप्त करने के लिए नियमित ऑडिट और मूल्यांकन आवश्यक है। यह केवल प्रारंभिक वेतन तक सीमित नहीं है, बल्कि वृद्धि, पदोन्नति, और अतिरिक्त लाभों तक विस्तारित है।
- द्वितीय, "अदृश्य श्रम" को मान्यता और मुआवजा मिलना चाहिए। गैर-प्रोन्नत कार्यों को पदोन्नति मानदंडों में शामिल किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों और स्कूलों में कार्यभार मॉडल में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सेवा कार्य का उचित मूल्यांकन और मान्यता हो।

- तृतीय, महिला शिक्षकों के लिए मेंटरशिप और व्यावसायिक विकास के अवसर सुनिश्चित किए जाने चाहिए। विशेष रूप से निम्न-आय वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों की महिला शिक्षकों के लिए लक्षित कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए।
- चतुर्थ, सागर जिले जैसे विशिष्ट भौगोलिक और सामाजिक संदर्भों में कार्यरत महिला शिक्षकों की आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बनाई जानी चाहिए। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात महिला शिक्षकों के लिए आवास, परिवहन, और सुरक्षा संबंधी प्रावधान शामिल हैं।
- पंचम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में लैंगिक संवेदनशीलता सुनिश्चित की जानी चाहिए। नीति के प्रावधानों को महिला शिक्षकों की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

महिला शिक्षकों की आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक योगदान एक जटिल और बहुआयामी विषय है, जो वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। यह समीक्षा स्पष्ट करती है कि महिला शिक्षकों के योगदान की पूरी श्रृंखला को समझने के लिए केवल उनके वेतन या शैक्षणिक योग्यता से परे देखना आवश्यक है। उनके अदृश्य श्रम, भावनात्मक योगदान, और सामुदायिक निर्माण की भूमिका को भी मान्यता मिलनी चाहिए।

सागर जिले का विशेष संदर्भ इस बात को रेखांकित करता है कि भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक कारक महिला शिक्षकों की स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की विशिष्ट चुनौतियाँ, जैसे जल संकट, कृषि अनिश्चितता, और पारंपरिक सामाजिक संरचनाएं, यहाँ की महिला शिक्षकों के जीवन और कार्य को एक विशिष्ट आकार प्रदान करती हैं।

इस समीक्षा का निष्कर्ष है कि महिला शिक्षकों की निरंतर हाशियाकरण को समाप्त करने के लिए उनके जीवित अनुभवों को ध्यान में रखना आवश्यक है। नीति निर्माण में न केवल सांख्यिकीय आंकड़ों बल्कि महिला शिक्षकों की आवाज़, उनके संघर्ष, और उनकी आकांक्षाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। केवल तभी हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं जो वास्तव में समावेशी, समतापूर्ण और न्यायसंगत हो।

भविष्य के शोध को सागर जिले और इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों में महिला शिक्षकों के जीवित अनुभवों का प्रत्यक्ष अध्ययन करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि नीतिगत प्रावधान वास्तविक जीवन में कैसे लागू होते हैं और उनका महिला शिक्षकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के अनुभवजन्य अध्ययन ही नीति निर्माण को अधिक प्रभावी और समावेशी बना सकते हैं।

संदर्भ सूची

1. Samuel, R. (2024). Positioning female teachers in the context of India. In *Low-*

Income Female Teacher Values and Agency in India: Implications for Reflective Practice (pp. 1-28). Bristol University Press.

2. Tharapos, M., O'Connell, B. T., Beatson, N., & de Lange, P. (2025). How do women accounting and finance professors develop and leverage their capitals for career advancement? *The British Accounting Review*, 101575.
3. Sutton, S. (2025). *The Evolution of Working Women's Needs: The Impact of Capitalism, Sexism, and the Feminization of Teaching on Four Generations of California Female Educators*. LMU Theses and Dissertations, 1323.
4. Winsten-Bartlett, C. Gendered Patterns of Resource Deprivation in Higher Education. *Journal of Higher Education Policy*.
5. Blanco, L. C. (2023). Cheated by academia: A review of the status of women in academia. *Revista de Ciencias Económicas*, 41(1), e51726.
6. Montano, S., Toral, I., & Percy, S. (2025). Invisible labour: visible activism. *SRHE Blog*.